

## भारत में कम्युनिस्ट पार्टियों का उदय एवं विकास

डॉ० गीतांजलि\*

1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में जबर्दस्त भूचाल आ गया। एक हिस्सा यह मानने को तैयार नहीं था कि कोई कम्युनिस्ट देश दूसरे देश पर आक्रमण करेगा। दूसरा हिस्सा चीन की इस कार्रवाई को सही नहीं समझता था। परिणामतः कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन हो गया। एक धड़ा कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हो गया और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से अलग पार्टी बना ली। 1964 में यह विभाजन हुआ था। दोनों पार्टियों ने अपनी अलग-अलग कांग्रेस आयोजित की और नये सिरे से दोनों ने अपनी नीति एवं सिद्धांत बनाये। उसके बाद दोनों पार्टियों ने अपनी नीतियों में कोई बदलाव नहीं किया है। नई आर्थिक नीतियों के संदर्भ में जरूर कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं।

आजादी के पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय क्रांति को दो चरणों वाली प्रक्रिया बताया जिसमें वर्तमान साम्राज्यवाद विरोधी, सामंत विरोधी चरण (एक राष्ट्रीय जनवादी चरण) के बाद पूंजीवाद विरोधी (समाजवादी) चरण आयेगा। पार्टी ने मोटे तौर से मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग एवं राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के राष्ट्रीय जनवादी मोर्चे की रणनीति का अनुसरण किया। 1947 में राष्ट्रीय आजादी की प्राप्ति ने भारत और विश्व के लिए एक नये युग, एक ऐतिहासिक घटना का सूत्रपात किया। यह भारत में एक अभूतपूर्व जन-उभार तथा विश्व में शक्तियों के नये सह-संबंधों का परिणाम था।

**क्रांति का नया चरण :-** यह राष्ट्रीय क्रांति की विजय का सूचक था, हालांकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जैसा सोचा था या अनुमान लगाया था उससे भिन्न घटना क्रम विकसित हुआ। देश का विभाजन हुआ जिसके गंभीर परिणाम सामने आये। फिर भी उसने भारतीय जनता के समाने राजनीतिक आजादी एवं राष्ट्रीय संप्रभुता को मजबूत करने और आर्थिक आजादी के लिए काम करने के वास्ते व्यापक अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हमारी जनता से क्रांति को एक नये चरण, एक आत्म-निर्भर, लोकतांत्रिक एवं गतिशील अर्थव्यवस्था का निर्माण करने तथा उसका नवीकरण करने, हमारी जनता के बेहतर जीवन स्तर को सुनिश्चित करने और लोकतंत्र के क्षेत्र का विस्तार करने एवं उसे समृद्ध करने, लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण करने तथा व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं एवं तेजी

\*एम.ए., पीएच.डी. इतिहास, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

से सांस्कृतिक प्रगति को सुनिश्चित करने के साम्राज्यवाद विरोधी और सामंत विरोधी कर्तव्यों को पूरा करने के चरण तक ले जाने की अपील की गई।

इस अवधि में महान उपलब्धियाँ हासिल की गईं, एक सार्वभौम राष्ट्रीय राज्य की प्राप्ति, बालिग मताधिकार एवं बहुदलीय प्रणाली के आधार पर चुनावों के साथ सरकार के संसदीय रूप तथा धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र पर आधारित एक संविधान का अपनाया जाना, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का अलगाव, एक संघीय किस्म की सरकार जिसमें केन्द्र तथा राज्यों को अधिकार आवंटित किये जायेंगे। सभी वर्गीय सीमाओं के साथ ये बड़े कदम हैं। राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष के दौरान अनेक बुनियादी पहलुओं पर एक आम सहमति कायम हुई। एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही है सामंती रजवाड़े राज्यों की समाप्ति, उनके भूतपूर्व प्रदेशों का पड़ोसी क्षेत्रों में विलय और भाषाई आधार पर और इस बहुभाषी, बहुराष्ट्रीय देश में जनता की आकांक्षाओं एवं लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप भारत का पुनर्गठन। यह वास्तव में नीचे से और ऊपर से क्रांति थी जिसमें टालमटोल एवं जनता के प्रयासों पर काबू पाया गया। शक्तिशाली तथा संयुक्त जनांदोलनों ने जिसमें कम्युनिस्टों ने अन्य ठोस सामंत विरोधी ताकतों के साथ प्रमुख भूमिका अदा की, इस ऐतिहासिक उपलब्धि को संभव बनाया, और भारत के राष्ट्रीय एकीकरण को आगे बढ़ाया गया और भाषाई एवं जातीय इकाइयों को राजनीतिक रूप से सुदृढ़ किया गया जिनमें उनकी पहचान को स्वीकार किया गया और इस तरह उनके लिए आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विकास की व्यापक संभावनाएँ उन्मुक्त की गईं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय पूंजीवादी नेतृत्व ने जिन्हें 1947 में विभाजित भारत में सत्ता हस्तांतरित की गई, संविधान तैयार करने और स्वतंत्र भारत के नये राज्य का निर्माण करने की पहल की। अंतर्विरोधों के जरिये राज्य मशीन एवं तंत्र का निर्माण किया गया और साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद के साथ समझौता किया गया। एक विशाल अति-केन्द्रीकृत तथा भारी-भड़कम राज्य मशीन निर्मित की गई है। एक विशाल देश का प्रशासन चलाने की प्रक्रिया में जिसका अत्यंत जटिल है, नौकरशाही, अति-केन्द्रीकरण, व्यापक भ्रष्टाचार, राजनीतिज्ञ, पुलिस-अपराधी गिरोह पर आधारित माफिया के बढ़ते ताने-बाने जो दोनों आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में काम करते हैं, के नकारात्मक पहलू भी विकसित हुए हैं।

आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक आजादी की दिशा में काफी प्रगति हुई है। दोनों उद्योग तथा कृषि क्षेत्र में उत्पादक शक्तियों का विकास हुआ है। उपनिवेशी अवधि के अनेक विदेशी प्रतिष्ठानों के राष्ट्रीयकरण, अत्यंत आवश्यक आधारभूत ढाँचे के निर्माण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण और अनेक भारी एवं बुनियादी और औद्योगिक परियोजनाओं के निर्माण में सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों में बड़ी सहायता मिली, जिससे इस प्रगति में काफी मदद मिली। मजबूत एवं विविधकृत सार्वजनिक क्षेत्र ने जिसका बुनियादी उद्योग आधार रहा है, एक

आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखी। लेकिन विकास के पूंजीवादी पथ ने जिसका अनुसरण किया गया है, सामाजिक ध्रुवीकरण में योगदान दिया है और असमानता बढ़ायी है। इजारेदार घरानों की परिसम्पत्ति कई गुना बढ़ गई है। उसके साथ ही छोटे एवं मध्यम उद्योग, खासकर लघु क्षेत्र काफी बढ़े हैं। अन्य दस या बारह प्रतिशत ने काफी समृद्धि हासिल की है जबकि 30 से 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। एकदम अपर्याप्त रोजगार के अवसरों, स्वरोजगार की सीमित संभावना, मूलगामी भूमि सुधार की तोड़फोड़ तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों की बंदी एवं छँटनी की वजह से बेरोजगारी में भारी वृद्धि होती रही है।

औद्योगिक विकास की दर धीमी हो रही है। योजना उलट-पुलट की गई है। देश का आंतरिक तथा विदेशी कर्ज काफी अधिक बढ़ गया है और हम कर्ज जाल के निकट पहुँच गये हैं। हाल का वित्तीय राजकोषीय संकट जो एकदम प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति में अभिव्यक्त हुआ, रोगसूचक था। बढ़ते बजटीय घाटे तथा असमान कर ढाँचे ने अधिकाधिक विकास के बोझ को आम लोगों पर डाल दिया है। वृद्धि तथा विकास में क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ गया है। राज्य के संसाधनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की लूट, विशाल कालाधन एवं विदेशी डिपॉजिट, मुनाफाखोरी और तस्करी व्यापक हो गई है।<sup>13</sup>

अपनी स्थापना के बाद से ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने समाजवाद को स्वतंत्र भारत के भावी विकास का लक्ष्य स्वीकार किया। इस लक्ष्य को सुसंगत लोकतंत्र के जरिये उपर्युक्त कर्तव्यों को पूरा करके ही हासिल किया जा सकता है। जब उपर्युक्त कर्तव्यों को पूरा किया जायेगा तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था उत्पादक शक्तियों के उच्च स्तर तथा उच्च उत्पादकता के साथ गतिशील, कारगर एवं स्व-उत्पादक होती जायेगी, जनता के मंगल कल्याण के लिए विज्ञान तथा प्रविधि की उपलब्धियों को आत्मसात करेगी और करोड़ों जनता की चहलकदमी को व्यापकतम संभावनाएँ प्रदान करेगी ताकि पिछड़ेपन की कठोर विरासत को दूर किया जा सके और हमारे विशाल भौतिक तथा मानव संसाधनों के पूर्ण इस्तेमाल के लिए परिस्थितियाँ निर्मित की जा सकें।

जब लोकतंत्र मजबूत होगा और उसका विस्तार होगा एवं जीवन के सभी क्षेत्रों में जनता को पूर्ण लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति प्रदान करेगा, सभी तरह के भेदभाव, असमानता तथा धर्म, जाति, लिंग एवं भाषा या जातियता के आधार पर सभी तरह के उत्पीड़न का उन्मूलन करेगा और उपर्युक्त प्रक्रियाओं में अधिकाधिक कारगर भूमिका अदा करेगा तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवाद का समर्थन करने वाली सभी अन्य शक्तियाँ भी मजबूत होंगी।<sup>14</sup> यह एक लम्बी अवधि होगी जिसके दौरान देश को अनेक राजनीतिक संरचनाओं एवं गठबंधनों के दौर से गुजरना होगा जिसके जरिये प्रतिक्रिया की ताकतें हासिल पर आ जायेगी और लोकतंत्र तथा समाजवाद की ताकतें अधिकाधिक ताकतवर होकर सामने आयेंगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपनी जिम्मेवारियाँ पूरी करते हुए अपने विचारधारात्मक राजनीतिक

आधार और जनाधार में भी काफी मजबूत होगी। इस तरह समाजवाद में संक्रमण के लिए वस्तुगत तथा आत्मगत परिस्थितियाँ परिपक्व होंगी।

इस पथ और भारतीय परिस्थितियों एवं वर्तमान ऐतिहासिक अवधि में समाजवाद की अवधारणा को पूरी सावधानी से विचार विमर्श करके पुनः परिभाषित किया जाना है। अभी यही कहा जा सकता है कि यह एक लोकतांत्रिक बहुसंरचनात्मक अर्थव्यवस्था के साथ जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र एक नेतृत्वकारी भूमिका अदा करेगा, मजदूर वर्ग के नेतृत्व में मजदूरों, किसानों, सभी अन्य मेहनतकश जनता, बुद्धिजीवियों और मध्यमवर्ग का राज्य होगा। किसान स्वामित्व को मूलगामी कृषि सुधार, कृषि विकास नीतियों के पूर्ण कार्यान्वयन और आर्थिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वेच्छिक कॉऑपरेटिवों को प्रोत्साहन के आधार पर फलने-फूलने की पूरी सुविधाएँ दी जायेंगी। औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन साधनों का सामाजिक स्वामित्व नेतृत्वकारी भूमिका अदा करेगा जबकि निजी क्षेत्र, कॉऑपरेटिव क्षेत्र, लघु क्षेत्र साथ-साथ कायम रहेंगे और पूरी अर्थव्यवस्था में पारस्परिक रूप से हाथ बँटायेंगे।<sup>15</sup> राज्य आर्थिक विकास को नियंत्रित करने और उसे बढ़ाने, जनता के मंगल कल्याण को बढ़ाने, शोषण समाप्त करने, सामाजिक एवं क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने, सार्वभौमिकता की रक्षा करने और आत्म-निर्भरता विकसित करने के लिए नियोजन की कार्यविधि का इस्तेमाल करेगा। यह मानवीय एवं न्यायोचित समाज होगा जिसमें सबों को समान अवसर प्रदान किया जायेगा तथा लोकतांत्रिक अधिकारों की गारंटी दी जायेगी जो मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का खत्म करने का मार्ग प्रशस्त करेगा, एक ऐसा समाज जिसमें मेहनतकश करोड़ों लोगों द्वारा उत्पादित धन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा नहीं किया जायेगा।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद के विज्ञान को सुसंगत लोकतंत्र और समाजवाद की दिशा में अपने पथ को निर्धारित करने के लिए अपरिहार्य समझती है। वह भारतीय समाज को समझने एवं उसमें परिवर्तन लाने के एक उपकरण के रूप में मार्क्सवाद प्रणाली को इस्तेमाल करने का प्रयास करती है। कमठमुल्लावादी तथा पुराने घिसे-पिटे विचार का परित्याग करते हुए वह अपना मार्ग निर्धारित करने के लिए इस विज्ञान तथा भारत की क्रांतिकारी विरासत से निर्देशित होती है जो हमारे देश की खास विशेषताओं, उसके इतिहास परम्पराओं, संस्कृति, सामाजिक संरचना तथा विकास के स्तर से निर्धारित होगा।<sup>16</sup>

वर्तमान भारतीय राज्य, बड़े पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व में, पूंजीपतियों और भूस्वामियों के वर्ग शासन का औजार है, जो पूंजीवादी विकास पथ पर चलते हुए, वित्तीय पूंजी के साथ उत्तरोत्तर सहयोग कर रहे हैं। देश के जीवन में, राज्य की भूमिका और काम को सारतः यही वर्ग चरित्र, निर्धारित करता है। यद्यपि यह माना जाता है कि हमारे राज्य का ढाँचा संघीय है, लेकिन प्रायः सारी सत्ता और संसाधन केन्द्र सरकार के हाथों में केन्द्रित है। यद्यपि प्रारंभ में बड़े पूंजीवादी वर्ग ने, भाषायी समरूपता के आधार पर प्रदेशों के गठन की मांग का प्रतिरोध किया, लेकिन जनांदोलनों व संघर्षों के भारी दबाव ने उसे भाषावार प्रदेशों के गठन के

लिए तैयार होने के लिए मजबूर कर दिया। भाजपा के नेतृत्ववाली सरकार ने, जो प्रशासनिक सुविधा पर आधारित छोटे-छोटे राज्यों की वकालत करती है, भाषावार राज्यों के सिद्धांत पर एक नया हमला बोला है। इससे संघीय ढाँचा और कमजोर होगा। निर्वाचित प्रदेश सरकारों को बर्खास्त करने और निर्वाचित प्रदेश विधायिकों को भंग करने के लिए, प्रकृति से ही अलोकतांत्रिक धारा 356 का केन्द्र द्वारा बारंबार इस्तेमाल, संघीय व्यवस्था के साथ भीतरघात करने और प्रदेशों की स्वायत्तता पर हमले करने का प्रमुख हथियार बना रहा है। संघ के संघटक राज्यों के पास मामूली शक्तियाँ ही हैं, जिसके कारण वे केन्द्र सरकार पर निर्भर रहते हैं और उनका विकास बाधित होता है।<sup>6</sup>

इन हालात में, केन्द्र सरकार और प्रदेशों के बीच के अंतर्विरोध बढ़ गए हैं, तो यह स्वाभाविक ही है। इन अंतर्विरोधों की तह में अक्सर, एक तरफ तो बड़े पूंजीवादी वर्ग और दूसरी तरफ राज्यों के पूंजीपति वर्ग व भूस्वामियों सहित वहाँ की जनता के बहुमत, के बीच के अंतर्विरोध होते हैं। पूंजीवाद के तहत, असमान आर्थिक विकास के चलते, यह अंतर्विरोध लगातार गहरा होता जाता है। इसी की राजनीतिक अभिव्यक्ति, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय में होती है, जो इन राज्यों की जनता की भाषायी जातीय भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं और आमतौर पर संबंधित क्षेत्र के पूंजीवादी भूस्वामी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

आजादी के बाद से लागू की जा रही, पूंजीवादी भूस्वामी नीतियों के कारण राष्ट्रीय एकता की समस्या गहरा गई है। देश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र जहाँ बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक राष्ट्रीयताएँ और उपजातीय समूह रहते हैं, इस पूंजीवादी विकास से पैदा हुए क्षेत्रीय असंतुलन और असमान विकास की सबसे ज्यादा मार झेल रहा है। इससे उग्रवादी तत्वों को फलने-फूलने के लिए उपजाऊ जमीन मिलती है। वे अलगाववाद की वकालत करते हैं और साम्राज्यवादी एजेसियों द्वारा उनका इस्तेमाल किया जाता है।<sup>7</sup> उग्रवादियों की हिंसक कार्रवाईयों और उपजातीय टकराव, विकास कार्यों और लोकतांत्रिक गतिविधियों में रूकावट डालते हैं। संविधान की धारा 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता व विशेष दर्जा दिया गया था। पिछले दशकों में, स्वायत्तता के प्रावधानों में भारी काट-छाँट हुई है और राज्य में जनता का बेगानापन बढ़ता गया है। इसका इस्तेमाल, पृथकतावादी ताकतों ने किया है, जिनको पाकिस्तान की मदद हासिल है। अमरीका के नेतृत्व में, साम्राज्यवाद, इस विवाद का इस्तेमाल भारत को दबाव में लेने और इस क्षेत्र में अपना दखल बढ़ाने के लिए करता है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और उसी तरह कश्मीर की भी समस्याएँ, राष्ट्रीय एकता के मसलों से लोकतांत्रिक ढंग से निपटने में पूंजीवादी भूस्वामी वर्गों की नाकामी की मिसालें हैं।

आदिवासी और जनजातीय जन, जिनकी आबादी सात करोड़ है, क्रूर पूंजीवादी और अर्द्धसामंती शोषण के शिकार हैं। जमीनें उनके हाथ से निकल गई हैं, जंगल पर अधिकार छिन गए हैं और वे ठेकेदारों तथा भू-स्वामियों के लिए

सस्ती और बंधुआ मजदूरी का स्रोत बन गए हैं। कुछ राज्यों में जनजातीय लोगों की बसाहटों के सघन इलाके हैं तथा उनकी अपनी खास भाषाएँ व संस्कृतियाँ हैं। जनजातीय जनता के बीच, अपनी पहचान व संस्कृति को बचाये रखने के साथ-साथ, जिंदगी की बेहतरी के लिए अपने अधिकारों की रक्षा की नई चेतना का उभार हुआ है। उनकी पहचान और अस्तित्व के लिए पैदा हुए खतरों तथा पूंजीवादी भूस्वामी शासकों की निष्ठुर नीतियों के कारण, जनजातीय लोगों के कुछ हिस्सों में, पृथकतावादी प्रवृत्तियाँ भी पनप गई हैं। ऐसे क्षेत्रों में जो परस्पर सटे हुए हैं तथा जहाँ आदिवासी बहुसंख्या में हैं, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग जायज और लोकतांत्रिक है। पूंजीवादी भूस्वामी ठेकेदार गठजोड़, उनके नेतृत्व को कुछ रियायतें देकर उनकी परम्परागत एकजुटता को भंग करने की बराबर कोशिश करता है, उन्हें जायज अधिकारों से वंचित करता है और उन्हें बर्बर ताकत के साथ कुचलता है।<sup>8</sup>

धार्मिक तत्त्ववाद, रूढ़िवाद, साम्प्रदायिकता और जातिवाद, अवाम को बाँटते हैं और उनकी जनवादी चेतना को कुंद बनाते हैं। पूंजीवादी राष्ट्रवाद और अंधराष्ट्रवाद के साथ ही, वे उन प्रतिक्रियावादी ताकतों द्वारा शोषित किये जाते हैं, जिन्हें जनवादी आंदोलन के विकास को छिन्न-भिन्न कर देने के लिए साम्राज्यवाद की मदद हासिल है। जनता की जनवादी सरकार की स्थापना, इस कार्यभारों के सफलता के साथ पूरे किए जाने और जनता के जनवादी राज्य में मजदूर वर्ग के नेतृत्व से यह सुनिश्चित होगा कि भारतीय क्रांति, जनवादी चरण पर ही नहीं ठहर जाएगी बल्कि उत्पादक शक्तियों के विकास के जरिये, समाजावादी रूपांतरण लाने के चरण में प्रवेश कर जायेगी।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), जनता के जनवाद की स्थापना के लिए अपना क्रांतिकारी कार्यक्रम, भारत के आवाम के सामने पेश करती है। जनता की जनवादी क्रांति, समाजवाद और एक शोषणविहीन समाज की तरफ आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगी। भारतीय जनता की मुक्ति के लिए इस क्रांति की अगुआई, किसानों के साथ गठबंधन बनाते हुए मजदूर वर्ग करेगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मजदूर वर्ग का अगुआ दस्ता होने के नाते कम्युनिस्ट पार्टी को साम्राज्यवाद, इजारेदार पूंजीवाद और भूस्वामी व्यवस्था के खिलाफ जुझारू संघर्षों का नेतृत्व करना है। देश में व्याप्त परिस्थितियों में, मार्क्सवाद-लेनिनवाद के सिद्धांतों को ठोस ढंग से लागू करते हुए पार्टी को राजनीतिक, वैचारिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी मोर्चों पर दीर्घकालिक संघर्ष चलाने होंगे, जब तक कि जीत नहीं हो जाती।

### संदर्भ—सूची

1. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यक्रम संबंधी दस्तावेज, कम्युनिस्ट पार्टी प्रकाशन, पृ. 3।
2. वही, पृ. 51। 3. वही, पृ. 51। 4. वही, पृ. 8। 5. वही, पृ. 8-14। 6. वही, पृ. 20-23। 7. वही, पृ. 23-26। 8. वही, पृ. 26-27।

